जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोनः- 2627612, 2427249 फैक्सः- 0145-2624665 | वर्षः 36 संख्याः 246 | प्रभात | अजमेर, बुधवार 15 अप्रैल, 2026 | आर.जे./ए.जे./73/2015-2017 | पृष्ठ 6 | मूल्य 2.50 रु.

महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने के लिए भाजपा को भारी विभाजन करना होगा विपक्ष में

चंद्रबाबू नायडू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। मोदी सरकार को महिलाओं के आरक्षण बिल को पारित कराने के लिए विपक्ष में बड़ी दरार डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके पास बिल पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है।

- जैसा प्रचारित है कि भारत के राज्य बहुत विचलित हैं, परिसीमन की प्रस्तावित प्रक्रिया से, क्योंकि, उत्तर भारत की सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी तथा दक्षिण भारत के राज्यों का राजनीतिक महत्व घट जाएगा, क्योंकि इन राज्यों की सीटें वर्तमान संख्या से कम हो जाएंगी।
- चंद्रबाबू नायडू दक्षिण भारत की जनभावना से जुड़ेंगे, पर, एनडीए का हिस्सा होने के कारण भाजपा का साथ देंगे, परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करेंगे।

बिल पारित करने के लिये 364 मत चाहिये, जबकि सत्तारुढ़ गठबंधन का संख्या बल 293 तथा विपक्षी सदस्य 240 है। अन्य सदस्य 11 है तता एक सीट खाली है।

विपक्ष के नेताओं की एक बैठक कल दोपहर 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास, 10 राजाजी मार्ग पर बुलाई गई है।

विपक्ष इस बैठक में तीन दिवसीय विशेष सत्र (16 से 18 अप्रैल) के दौरान सरकार के खिलाफ महिलाओं के आरक्षण बिल पर विचार -मंथन एवं रणनीति तय करेगा।

विपक्ष यह तर्क दे रहा है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित सीटों में वृद्धि अवैज्ञानिक और मनमानी भरा प्रयास है।

इसके साथ ही, वे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ओबीसी महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोई जाति जनगणना नहीं हुई है और सरकार वास्तविक और उचित जाति डेटा के बिना परिसीमन (डीलिमिटेशन) करने का प्रस्ताव रख रही है।

मीटिंग में सभी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया गया है, और अधिकांश के आने की उम्मीद है, विशेष रूप से दक्षिण भारत की पार्टियों से।

यहाँ एक बड़ा सवाल चंद्रबाबू नायडू की भूमिका को लेकर है, जो एनडीए में भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं।

देखना यह है कि क्या नायडू विपक्ष का साथ देंगे, खासकर इस स्थिति में, जब दक्षिण भारत में सरकार द्वारा दक्षिण को हाशिए पर रखने के तरीके से काफी गुस्सा है।

चंद्रबाबू को अपने और अपने दल के राजनीतिक भविष्य के बारे में भी सोचना होगा।

विपक्ष के नेताओं में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि सरकार ने महिलाओं के आरक्षण बिल को आज सदस्यों को भेजा है, जिससे उन्हें बिल का विस्तार से अध्ययन करने का समय नहीं मिला।

विपक्ष इसे अनुचित (मैलाफाइड) बता रहा है और कह रहा है कि इसका उद्देश्य लोकसभा को रबर स्टाम्प में बदलना है, बजाय इसके कि सांसद अपने विचारों को उचित अध्ययन के बाद व्यक्त करें।

विपक्ष संभवतः राज्यसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार पर भी चर्चा करेगा।

आरजेडी सांसद मनोज झा का नाम इस पद के लिए चल रहा है, क्योंकि उनके पास काम को संभालने का ज्ञान और सम्मान, दोनों हैं।

लोकसभा में पिछले कई वर्षों से उपसभापति नहीं है, और इससे सदन में समस्याएँ पैदा हुई हैं, जैसा कि तब सामने आया, जब सभापति ओम बिड़ला अविश्वास प्रस्ताव के परिणाम का इंतजार करते हुए, सदन की अध्यक्षता नहीं कर रहे थे।

ट्रंप ने मोदी को फोन किया

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बीच आज मंगलवार की शाम को लगभग 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान पश्चिम एशिया संकट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समेत, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीजफायर और अमेरिका-ईरान के बीच वार्ता विफल होने के बाद, यह दोनों नेताओं की पहली बातचीत है।

पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर की है। पीएम मोदी ने लिखा, मेरे मित्र, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का फोन आया। हमने विभिन्न क्षेत्रों में अपने द्विपक्षीय सहयोग में हुई उल्लेखनीय प्रगति की समीक्षा की।

- पश्चिम एशिया, होर्मुज़ आदि विषयों पर 40 मिनट बात की।

पीएम मोदी और डॉनल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत पर भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत आधार पर टिके हैं।

इस बातचीत की जानकारी देते हुए गोर ने बताया कि ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा, मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर के बाद पहली बार ट्रंप और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका-ईरान ''फेल्ड'' वार्ता पुनः शुरु होगी गुरुवार को?

सूत्रों के अनुसार, पर, अभी यह तय नहीं हुआ है कि वार्ता कहाँ होगी, इस्लामाबाद में या जिनेवा में

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रेल। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को इस्लामाबाद में 21 घंटे की आमने-सामने की वार्ता हुई, जो कोई समझौता हुए बिना ही खत्म हो गई, जिससे दो सप्ताह की नाज़ुक युद्धिवराम की स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है।

- ट्रंप ने मीडिया को बताया कि दूसरी पार्टी (ईरान) ने उनसे सम्पर्क किया है कि वे एक ''डील'' (सौदा) करना चाहते हैं, हमसे।
- अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, ईरान उनके दिशा में मुड़ा है, पर, पूरी तरह से नहीं, अतः वार्ता टूटी थी।
- वैंस के अनुसार, जब वार्ता टूटी थी उससे पहले पूरी आशा बनी थी कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो जाने वाला है, पर, अचानक कुछ बदल गया और वार्ता ''फेल'' हो गई।

इस्लामाबाद वार्ता विफल होने के बाद, अमेरिका और ईरान के बीच नई वार्ता का दौर गुरुवार को हो सकता है, इससे पहले कि दोनों युद्धरत देशों के बीच दो सप्ताह का युद्धिवराम समाप्त हो। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने जल्द ही व्यक्तिगत वार्ता फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है, बशर्ते उन्हें लगे कि तेहरान उनकी मांगों के अनुसार तैयार है।

अमेरिकन अफसर व एक राजनयिक ने कहा, यह स्पष्ट नहीं है कि नई वार्ता में उसी स्तर के प्रतिनिधि उपस्थित होंगे या नहीं। रिपोर्ट के अनुसार, नई वार्ता के लिए इस्लामाबाद और जिनेवा संभावित स्थल हैं।

एसोसिएटेड प्रेस ने कहा, वॉशिंगटन और तेहरान आमने-सामने वार्ता में नए व्यक्तियों को लाने पर विचार कर रहे हैं, ताकि छह सप्ताह के युद्ध को समाप्त करने का समझौता किया जा सके, इससे पहले कि युद्धिवराम 21 अप्रैल को समाप्त हो।

तीन स्त्रोतों ने अमेरिकी एजेंसी को बताया कि नई वार्ता के बारे में अभी भी मंत्रणा चल रही है, जबकि एक मध्यस्थ देश के राजनयिक ने आगे आकर कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन इस पर सहमत हो गए हैं।

एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जगह और समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन वार्ता गुरुवार को हो सकती है।

जब ट्रम्प ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि ''हमें दूसरी तरफ से बुलाया गया है और वे एक समझौते पर काम करना चाहते हैं,'' इसके बाद यह बयान आया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आरजी कर पीड़िता की माँ को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंकी भाजपा ने

भाजपा ने कोलकाता की समीपवर्ती पनिहाटी सीट से आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार पीड़िता की माँ रत्ना देबनाथ को टिकट दिया है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। पनिहाटी विधानसभा क्षेत्र, जो उत्तर 24 परगना जिले का हिस्सा है, कोलकाता से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यहीं से भाजपा ने उस महिला डॉक्टर की माँ रत्ना देबनाथ को मैदान में उतारा है, जिनके साथ लगभग दो साल पहले आरजी कर अस्पताल में बलात्कार हुआ और उनकी जघन्य हत्या कर दी गई थी। जिसने राज्य को गुस्से से भर दिया था और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा हो गया था।

- रत्ना देबनाथ का कहना है, उन्होंने भाजपा को चिट्ठी लिखकर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी और उनकी यह जीत उनकी मृत बेटी व राज्य की सभी महिलाओं की जीत होगी।
- भाजपा इस चुनाव को बहुत महत्व दे रही है, यहाँ से भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने मोर्चा संभाल रखा है, वे नामांकन भरने के समय भी रत्ना देबनाथ के साथ थीं।

रत्ना देबनाथ एक सामान्य महिला हैं, जिनका राजनीति से कोई पूर्व संबंध नहीं है। फिर भी अब वे चुनाव मैदान में हैं। भाजपा ने उनके पीछे पूरी ताकत लगा दी है, जिसका संकेत अप्रैल 9 को नामांकन दाखिल करने के समय पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी से भी मिलता है।

स्मृति ईरानी के माध्यम से, भाजपा महिला मतदाताओं को एकजुट करने का काम जोर-शोर से कर रही है। पूर्व मंत्री बंगाली भाषा में निपुण हैं और बंगाल में अपने चुनावी भाषण केवल इसी भाषा में दे रही हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने उन्हें टिकट देने के लिए संपर्क

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सम्राट चौधरी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे

पटना, 14 अप्रैल। बिहार में राजनीतिक बदलाव के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एनडीए ने नई सरकार गठन का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश कर दिया है। भाजपा विधायक दल और राजग विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ गई है।

- बुधवार 15 अप्रेल को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है।

मंगलवार शाम एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ सम्राट चौधरी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सैयद अता हसनैन से मुलाकात की और सरकार गठन का दावा प्रस्तुत किया। राज्यपाल ने इस दावे को स्वीकार कर लिया है। 15 अप्रैल (बुधवार) सुबह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नीतीश के बाद बिहार में क्या कोई भारी बदलाव होगा?

इस सवाल के मूल में है कि जेडी (यू) की सीटें भाजपा से 4 ही कम है और फिलहाल जेडी (यू) नीतीश के पक्ष में एकजुट है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल।

पचास साल से ज्यादा के इंतजार के बाद, बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भाजपा का उम्मीदवार बिहार में मुख्यमंत्री बनेगा, जब सम्राट चौधरी बुधवार को इस सर्वोच्च पद की शपथ लेंगे। जनसंघ, जो भाजपा का पुराना स्वरूप था, ने 1962 में पहली बार तीन विधानसभा सीटें जीती थीं।

लगभग दो दशक तक सत्ता में रहने के बाद, नीतीश कुमार ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। नई सरकार अभी भी गठबंधन सरकार होगी, लेकिन इस बार इसका नेतृत्व भाजपा के उम्मीदवार के हाथ में होगा। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में क्या बदलाव आएंगे?

नीतीश कुमार ने, अपनी अवसरवादी राजनीति के बावजूद, अच्छे शासन का एक मॉडल स्थापित किया और ऐसा भी देखा गया कि उन्होंने भाजपा को कठोर हिन्दुत्व राजनीति अपनाने से रोका। अब, एनडीए गठबंधन के मुख्य साझेदार के रूप में,

- इसलिए जानकारों की माने तो फिलहाल तो भाजपा नीतीश स्टाइल की ही ''सोशल वैलफेयर'' नीति पर ही चलेगी। हालांकि अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश अवश्य करेगी।
- इसके अलावा बिहार में समाजवादी सोच की जड़ें बहुत गहरी है, जिससे एकाएक हटाना संभव नहीं है।
- तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार का ''एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड क्लास'' (ईबीसी) और महिलाओं में बड़ा भारी प्रभाव है और भाजपा इसे कदापि खोना नहीं चाहेगी।
- भाजपा के सम्राट चौधरी भले ही बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, पर, जनता में प्रभाव व राजनैतिक अनुभव की बात करें तो सम्राट चौधरी का नीतीश से कोई मेल नहीं है, नीतीश का कद बहुत ऊंचा है।

क्या भगवा पार्टी 'बुलडोजर राजनीति', 'एंटी-रोमियो अभियान' या 'लव जिहाद' जैसे कदमों के जरिए हिन्दुत्व अभियान को तेज़ करेगी?

क्या भाजपा के जातिगत समीकरणों और हिन्दुत्व एजेंडे के कारण नीतीश कुमार की सामाजिक कल्याण नीति पीछे हट जाएगी?

बिहार के राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा इस अवसर का उपयोग राज्य में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए करेगी, लेकिन अपेक्षाकृत इस छोटे कार्यकाल में नीतीश कुमार की राजनीतिक विचारधारा से भटकने की संभावना कम है। इसके कई कारण हैं। पहला, राज्य विधानसभा में जेडीयू की सदस्य संख्या भाजपा से केवल 4 कम है, इसलिए कुमार की पार्टी तुरंत समाप्त नहीं होने वाली।

दूसरे, समाजवादी विचारधारा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक के आरोपी को हाई कोर्ट से जमानत मिली

जयपुर, 14 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस चन्द्र प्रकाश श्रीमाली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी अशोक कुमार की द्वितीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पेपर लीक प्रकरण में जो आरोप याचिकाकर्ता पर है, वह समान आरोप उस आरोपी पर भी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित है।

- हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि समान आरोप वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 20 साल का ''फ्रीज़'' करवाना चाहता है, तेहरान पाँच साल का ''फ्रीज़'' पर अड़ा है

अमेरिका ने शुरु में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम यूरेनियम को कतई बंद करवाने की शर्त रखी थी, पर, फिर बदलाव आया अमेरिका की सोच में और अमेरिका ने बीस साल तक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ''फ्रीज़'' करने का प्रस्ताव दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 14 अप्रैल। रिपोर्टों के अनुसार, तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन को पांच साल तक निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव को ट्रम्प प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया और 20 साल के विराम की मांग कर रहा है।

ईरान की परमाणु गतिविधियों को लेकर पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की सप्ताहांत वार्ता का केन्द्रीय मुद्दा थी।

- जैसा कि विदित ही है, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सैन्ट्रल मुद्दा था, जिस पर अमेरिका-ईरान वार्ता टूटी थी।
- वार्ता टूटने के बाद भी छुटपुट विचारों का आदान-प्रदान जारी रहा तथा ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाँच साल तक ''फ्रीज़'' करने का प्रस्ताव दिया, पर, अमेरिका बीस साल तक ''फ्रीज़'' रखने पर जोर देता रहा।
- पोलिटिकल साइंटिस्ट इयान ब्रेमर का मानना है कि अमेरिका व ईरान संभवतया बारह साल छः महीने की ''फ्रीज़'' पर एग्रीमैंट करने को रज़ामंद हो जाएंगे। चाहे अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर पूर्ण ''ब्लॉकेड'' करने की घोषणा भी कर दी हो।

वॉशिंगटन ने अपने प्रस्ताव में ईरान के यूरेनियम संवर्धन पर 20 साल के विराम का प्रस्ताव रखा, लेकिन तेहरान ने कहा कि वह केवल पांच साल तक ही ऐसा कर सकता है, यह जानकारी ''द न्यूयॉर्क टाइम्स'' और ''वाल स्ट्रीट जर्नल'' ने दी है।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद वार्ता के दौरान ईरानी परमाणु गतिविधियों के निलंबन पर प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया, लेकिन किसी भी समझौते की अवधि पर दोनों पक्ष अभी भी दूर हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों और एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया, तेहरान ने पांच साल तक यूरेनियम संवर्धन निलंबित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे ट्रंप प्रशासन ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता की सुनवाई करे

जयपुर, 14 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2012 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक लाने के बावजूद, अभ्यर्थी का चयन नहीं करने के मामले में राज्य सरकार को कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से मामले में दिए निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन तय करे। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश सोनम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- शिक्षक भर्ती 2012 के संशोधित परिणाम में अधिक अंक लाने के बाद भी याचिकाकर्ता का चयन नहीं हुआ था।

याचिका में अधिवक्ता विजय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)